यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता

2941. **श्री अजीत जोगी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पुनर्वास कार्य हेतु राज्य को अन्य स्रोतों से भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त कोई सिंचाई परियोजना नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए गुजरात को आबंटित धनराशि

2942. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए गुजरात सरकार को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर खर्च किये गये परिव्यय की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1994-95 के लिए गुजरात राज्य में सिंचाई हेतु 596.83 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ख) विश्व बैंक सहायता से सरदार सरोवर परियोजना के अलग हो जाने के परिणामस्वरूप, इस परियोजना को पूरा करने के वास्ते 550 करोड़ रुपए की सहायता की सहमति हुई है।

(ग) और (घ) चूंकि सिंचाई राज्यों का विषय है और परियोजनाओं के लिए निधियां राज्य सरकार द्वारा निर्मुक्त की जाती हैं, गुजरात में सिंचाई हेतु वर्ष 1992–95 की अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय, आठवीं योजना के 3756.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले, 1554.64 करोड़ रुपये है।

Unutilized Irrigation Projects

2943. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although many unutilised irrigation projects have been constructed, yet no benefits from them have been derived as the distribution canal system has not been undertaken, if so, what are the reasons for such a state of affairs;

(b) whether it is also a fact that the biggest single malady in the major and medium irrigation sector, right from the First Plan, has been the tendency to start more new projects without completing the ones in hand;

(c) if so, the reason therefor; and

(d) what steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. There are instances where storage/diversion facility has been created but the work on construction of distribution system is lagging behind with the result that full benefits could not be derived from such projects. The main reasons for non-completion of distribution system are problems in acquisition of land and paucity of funds.

(b) Yes, Sir.

(c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, formulated and implemented by the State Governments out of their own plan resources.

(d) To ensure accrual of benefits from investment, the strategy adopted in the VIII Plan is to attach top most priority to completion of on-going projects which have made significant progress in implementation. The Planning Commission has started strict earmarking of outlays to important projects. Further, the Central Water Commission has been entrusted with monitoring of selected projects.

उत्तरी कोयल नहर परियोजना

2944. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उत्तरी कोयल नहर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा केन्द्र सरकार ने वर्ष 1994 के लिए इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी राशि दी है ;

(ख) इस परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है और वर्तमान में इस नहर परियोजना के अन्तर्गत कितने हेक्टर भूमि में सिंचाई की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार ने 1993-94 और 1994-95 में इस परियोजना के लिए राज्य सरकार को कोई राशि दी है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर कोयल नहर परियोजना की भौतिक प्रगति, सिंचाई क्षमता और वित्तीय स्थिति इस प्रकार है :—

घटक	पूरा किया गया कार्य
भौतिक	
1. कुटकु बांध . .	93%
2. द्वार का निर्माण . .	80%
3. मोहम्मद गंज बराज . .	99%
4. बराज पर पुल . .	शून्य
5. मुख्य नहर	
(क) बायां तट नहर .	8%
(ख) पक्का करने का कार्य	शून्य
(ग) दायां तट नहर . .	97%
(घ) पक्का करने का कार्य	79%
6. **वितरण प्रणाली**	
(क) मिट्टी कार्य . .	34%
(ख) पक्का करने का कार्य	22%
(ग) जल निकास . .	9%

सिंचाई क्षमता : 104.72 हजार हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता की तुलना में 33.06 हजार हेक्टेयर क्षमता का सृजन किया गया है और लगभग 20.00 हजार हेक्टेयर का उपयोग किया जा रहा है।

वित्तीय : इस परियोजना की अनुमानित लागत 475 करोड़ रुपये है। जून, 1994 तक 361.37 करोड रुपए का व्यय किया गया है। योजना आयोग के कार्य दल ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए परिव्ययों की सिफारिश की है जो इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रावधान (करोड़ रुपए)	व्यय (करोड़ रुपए)
1993-94	22.00	11.32
1994-95	17.00	2.21 (जून, 1994 तक)

वर्तमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, क्रियान्वयन तथा वित्त पोषण स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र एक मुश्त अनुदान तथा ऋण देता है जो किसी क्षेत्र से जुड़ा नहीं होता है।

National Institute for Research and Training in the Field of Ground Water

2945. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :

SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a National Institute for Research and Training in the field or ground water in the country;

(b) if so, the objectives in setting up such an Institutes;

(c) whether any survey has been made to identify the areas ; and

(d) if so, what are the details thereof, stating the estimated cost likely to be incurred thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON : (a) Yes, sir;

(b) The objectives of the Institute are to create facilities for training national and international professionals and sub-professionals at the induction, mid-career, senior and management levels in all relevant aspects of ground water investigation, exploration, assessment, planning, development, management, conservation and protection.

(c) and (d) After taking into consideration the recommendations of the Site Selection Committee and other relevant factors, the Government have decided to set up the Institute at Raipur. The revised estimated cost for establishing the Institute is Rs. 832.00 lakhs.